AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारतः रक्षा–निर्यातक देश बनने की दिशा में अग्रसर

ORIGINAL ARTICLE

Authors

डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग

डॉ. प्रवीण कुमार कड़वे
सहायक प्राध्यापक, रक्षा अध्ययन विभाग

एवं

डॉ. गीतांजलि चन्द्राकर
रक्षा अध्ययन विभाग
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

इस वर्ष भारत के रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में राशि रुपये 3,000.00 करोड़ से ज्यादा का रक्षा निर्यात हुआ है जिसमें बड़े शस्त्रों से लेकर छोटे उपकरण शामिल है, इसके अलावा रक्षा उत्पादन का भी रिकॉर्ड टूटा है। इस वर्ष एक लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन हुआ है, इन दोनों आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष पूरी दुनिया से LCA – तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य सामग्रीयों की मांग रही है। भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत ज्यादातर सामग्रीयों, हथियारों, उपकरणों को भारत में ही निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत की सीमा सुरक्षा बढ़ी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 में करीबर राशि 16,000.00 करोड़ का रक्षा निर्यात हुआ है, यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रुपये 3,000.00 करोड़ ज्यादा है, जबकि वर्ष 2016–17 की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। भारत इस समय अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी समेत 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही है इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लांचर तक है।

मुख्य शब्द

रक्षा उत्पादन, रक्षा निर्यात, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, नवाचार प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता.

प्रस्तावना

भारत के रक्षा परिदृश्य में पिछले एक वर्ष में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह हुआ है कि भारत अब शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ गया है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023 को एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में चिन्हित किया है, जब रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। भारत का रक्षा निर्यात राशि रुपये 16,000.00 करोड़ तक पहुंच गया जो इसके एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग राशि रुपये 3,000.00 करोड़ अधिक है। इसके अलावा समवर्ती रुप से रक्षा उत्पादन में पहली बार राशि रुपये एक लाख करोड़ के महत्वपूर्ण मील के पत्थर

को पार कर लिया है।

*(**Source:** MyGov.in)*

भारत की रक्षा रणनीति में स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर देना एक सतत प्रयास रहा है। ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र ने विदेशी रक्षा आयात पर निर्भरता से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की ओर धीरे–धीरे परिवर्तन देखा है। वर्ष 2014 में शुरू की गई ''मेक इन इंडिया'' पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना था जिसमें रक्षा सहित सभी क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने नवाचार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों में और सुधार पेश किए गए हैं।

पिछले वर्ष की गतिविधियों पर दृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि सरकार की प्रयासों का लाभ मिल रहा है। सरकार को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि अब पहले की तुलना में डी.आर.डी.ओ. से विकसित अधिक प्रणालियों की खरीद की जा रही है। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का नारा रक्षा उत्पादन और रक्षा क्रय के विषयों में स्पष्ट दिखाई देता है, इसके साथ ही ''मेक इन इंडिया'' की नीति पर बल दिया गया है। औद्योगिक संगठनों के अनुसार आवश्यकता की स्वीकार्यता यानी एओएन के 80–90 प्रतिशत विषय भारतीय कंपनियों से संबद्ध है। इस राशि का लगभग 60–70 प्रतिशत हिस्सा भारतीय डिजाइन, विकास, निर्माण श्रेणी की रक्षा क्रय पर होता है।

निजी क्षेत्र

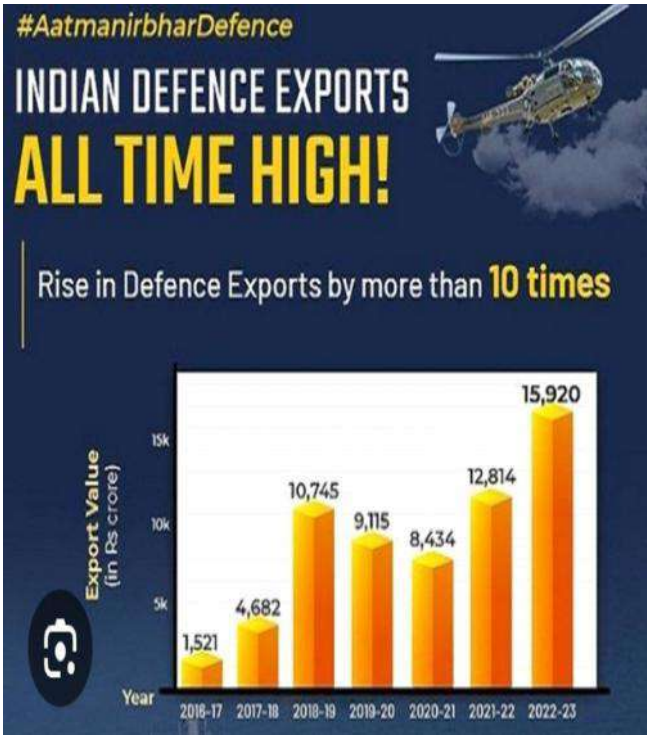

*(**Source:** MyGov.in)*

वर्ष 2020 की रक्षा क्रय नीति में इसे सर्वाधिक प्राथमिकता वाली श्रेणी में रखा गया है। वास्तविक संदर्भ में सेना की कुल वार्षिक रक्षा उपकरण क्रय लगभग राशि रूपये 1.08.00 लाख करोड़ की रहती है। इसमें से लगभग राशि रूपये 20–21 हजार करोड़ के शस्त्र निजी क्षेत्र तैयार करता है। ऐसी प्रमुख निजी कंपनियों में भारत फोर्ज जैसी कंपनियां हैं, जो कल्याणी समूह की रक्षा कंपनी है। इसका टर्नओवर राशि रुपये 1,400–1,500 करोड़ है और उसके पास राशि रुपये 4,500.00 करोड़ के क्रय आदेश हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो तथा गोदरेज एंड बॉयस आदि ऐसे ही कुछ और नाम है।

रक्षा निर्यात में भी निजी क्षेत्र की भूमिका बड़ी है। वह पहले ही पड़ोसी देशों को वाहनों, प्लेटफॉर्म तथा छोटे युद्धपोतों की बिक्री में हस्तक्षेप बना चुका है। वर्ष 2017–18 में जहां राशि रूपये 4,682.00 करोड़ मूल्य का निर्माण किया गया था वहीं वर्ष 2018–19 में यह बढ़कर

राशि रूपये 11,000.00 करोड़ हो गया है।

(करोड़ रुपये में)

वित वर्ष	कुल निर्यात मूल्य
2016–17	1,521
2017–18	4,682
2018–19	10,745
2019–20	9,115
2020–21	8,434
2021–22	12,814
2022–23	15,920

*(**Source:** pib.gov.in)*

चालू वित्त वर्ष का निर्यात राशि रूपये 16,000.00 करोड़ से भी ज्यादा होगा क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल, रॉकेट लांचर एटीएजीएस हॉवित्जर तोपो और तेजस लड़ाकू विमान तथा ध्रुव हल्के हेलीकॉप्टरों की बिक्री बढ़ रही है। इस बात की भी उम्मीद है की रक्षा मंत्रालय वर्ष 2018 की रक्षा उत्पादन नीति में उल्लेखित वर्ष 2025 तक राशि रूपये 35,000.00 करोड़ के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर सकता है। निर्यात वृद्धि का यह स्तर भारत को राशि रूपये 1.8.00 लाख करोड़ के वार्षिक रक्षा उत्पादन कारोबार के लक्ष्य के साथ दुनिया के सिर्फ पांच रक्षा उत्पादकों में से एक बनने के वर्ष 2018 के राष्ट्रीय रक्षा नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। रक्षा निर्यात की इस वृद्धि के रक्षा आयात में कमी करने की आवश्यकता भी है।

वैश्विक मांग

भारत की रक्षा सामग्री की वैश्विक मांग में वृद्धि हो रही है। रक्षा मंत्रालय के संचालन के मूल में रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना, सीमा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, नारी शक्ति का दोहन करना और पूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करना था। भारत अब अपने रक्षा उद्योग की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 85 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। लगभग 100 कंपनियां सक्रिय रूप से रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही है जिसमें डॉर्नियर –228, 155 मिमी उन्नत टोड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल और विभिन्न अन्य परिष्कृत रक्षा प्रणालियां सम्मीलित है। सूची में अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार और गोलाबारी भी सम्मीलित किया गया है। इन सभी वस्तुओं को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया वर्ष 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रमबद्ध समय सीमा में स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। सैनिक विषयों के विभाग (डी एम ए) ने पहले 4 सूचियॉ जारी की थी जिसमें 411 सैन्य वस्तुएं सम्मिलित थी। अलग से, रक्षा उत्पादन विभाग (डी. डी. पी.) ने चार सूचियॉ जारी की, जिनमें कुल 4,666 आइटम सम्मिलित है, जिसमें डीपीएसयू के लिए लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट/सब सिस्टम /स्पेयर और घटक सम्मिलित है। 928 वस्तुओं की सूची भी पिछले वर्ष डी. डी. पी. द्वारा जारी की गई थी।

इस दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और एम.एस.एम.ई. और स्टार्टअप को आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने की व्यवस्था भी हुई। खासतौर से वित्त वर्ष 2023–24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 प्रतिशत लगभग राशि रूपये 1.00 लाख करोड़, आवंटित किया गया था। चालू वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय को कुल राशि रूपये 5.94 लाख करोड़ का बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जो कुल बजट का 13.18 प्रतिशत है आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी परिव्यय बढ़कर राशि रूपये 1.63 लाख करोड़ हो गया हैं।

रक्षा निर्यात कीर्तिमान

लगातार नीतिगत पहलू और रक्षा उद्योग के जबरदस्त योगदान के माध्यम से, रक्षा निर्यात लगभग सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 16,000.00 करोड़ का निर्यात हुआ जो पिछले वित्त

वर्ष की तुलना में लगभग राशि रूपये 3,000.00 करोड़ अधिक है। वर्ष 2016–17 के बाद से इसमें 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई भारत और 85 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है।

भारतीय उद्योग में दुनिया को अपनी डिजाइन और विकास की क्षमता दिखाई है, वर्तमान में 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही है। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख प्लेटफार्मो में डोर्नियर –228, 155 मिमी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट और लांचर, गोला बारूद, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्मर, सिस्टम के अलावा सम्मीलित है।

चालू वित्त वर्ष 2023–24 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 प्रतिशत (लगभग राशि रूपये 100.00 करोड़) घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया था, जो वर्ष 2022–23 में 68 प्रतिशत से अधिक है। वित्त वर्ष 2023–24 में रक्षा मंत्रालय को कुल राशि रूपये 5.94 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जो कुल बजट (राशि रूपये 45.03 लाख करोड़) का 13.18 प्रतिशत है। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास में संबंधित पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर राशि रूपये 1.63 लाख करोड़ कर दिया गया है।

रक्षा उत्पादन कीर्तिमान

वित्त वर्ष 2022–23 में रक्षा उत्पादन पहली बार राशि रूपये एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। वित्त वर्ष 2021–22 में यह राशि रूपये 95.00 हजार करोड़ था। सरकार रक्षा उद्योगों और उनके संगठनों के साथ लगातार काम कर रही है ताकि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके और देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं जिसमे आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित उद्योग रक्षा डिजाइन विकास और विनिर्माण में आगे आ रहे हैं और पिछले 7 से 8 वर्षों के उद्योगों को जारी किए गए रक्षा लाइसेंस की संख्या में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गश्ती पोत

रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन, रक्षा मंत्रालय ने लगभग कुल लागत पर 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपयार्ड के साथ अनुबंध कर हस्ताक्षर किए राशि रूपये 19,600.00 करोड़ क्रय (भारतीय आईडीडीएम) श्रेणी के तहत 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों के अधिग्रहण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स (जी आर एस ई), कोलकाता के साथ अनुबंध कर हस्ताक्षर किए थे। 11 जहाजों में से सात को जीएसएल द्वारा और चार को जीआरएसई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित किया जाएगा। जहाजों की डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है। राशि रूपये 9,850 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी के 6 मिसाइल पौधों की क्रय के अनुबंध पर कोचिंन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। जहाजों की डिलीवरी मार्च 2027 से शुरू होने वाली है।

*(**Source:** INS Savitri)*

बेड़ा सहारा पोत

रक्षा मंत्रालय ने लगभग राशि रूपये 19,000.00 करोड़ की कुल लागत पर भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़ा सहारा जहाज (एफ.एस.एस.) के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

*(**Source:** INS Nireekshak)*

एफ.एस.एस. को समुद्र में जहाजों को ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडार से भरने के लिए नियोजित किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना बड़े को बंदरगाह पर वापस आए बिना लंबे समय तक काम करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। इन्हें लोगों को निकालना और एच. डी.आर. संक्रिया के लिए भी तैनात किया जा सकता है। 44,000 टन के जहाज किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में बनाए जाने वाली अपनी तरह के पहले जहाज होंगे यह परियोजना 8 वर्षों की अवधि में लगभग 168.8 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा करेगी।

सुरंग

बीआरओ 20 सुरगों पर काम कर रहा है, जिसमें से 10 निर्माणाधीन है और 10 योजना चरण में हैं। बीसीटी रोड (अरुणाचल प्रदेश) पर 500 मीटर लंबी नेचिफू सुरंग सितंबर में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। इसके अलावा 4.8 किलोमीटर लंबी शिंकू ला सुरंग का निर्माण जल्द ही शुरू होने की संभावना है, जो पूरा होने के बाद 15,855 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी।

*(**Source:** bhaskar.com)*

*(**Source:** bhaskar.com)*

*(**Source:** Sela Tunnel pib.gov.in)*

अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा–चारदूआर–तवांग रोड पर सेला सुरंग परियोजना ट्विन ट्यूब कॉन्फिगरेशन की दो सुरंगे हैं। यह सुरंग संरेखण यात्रा को की दूरी को 8 किलोमीटर कम कर देगी। इसके अलावा सेला दर्रे की चढ़ाई को कम करते हुए यात्रा के समय को 1 घंटे काम कर देगी, जिससे तवांग के लिए सभी मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी।

निष्कर्ष

भारत की रक्षा रणनीति में स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर देना एक सतत् प्रयास रहा है। ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र ने विदेशी रक्षा आयात पर निर्भरता से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की ओर धीरे–धीरे बदलाव देखा है। वर्ष 2014 में शुरू की गई ''मेक इन इंडिया'' पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना था जिसमें रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और सुधार किए गए हैं।

संदर्भ सूची

1. Defence Monitor, Vol.-12, Issue-3,Feb.-March 2024.
2. https://www.businesstoday.in, Assess on January, 08, 2024.
3. https://bhaskar.com, Assess on January, 03, 2024.
4. https://www.ddpmod.gov.in, Assess on January, 09, 2024.
5. https://defenceexam.gov.in, Assess on January, 09, 2024.
6. https://indbiz.gov.in, Assess on January, 04, 2024.
7. https://www.makeinindiadefence.gov.in, Assess on January, 04, 2024.
8. https://www.orfonline.org, Assess on January, 10, 2024.
9. https://www.pib.gov.in, Assess on January, 10, 2024.
10. https://www.thehindu.com, Assess on January, 10, 2024.

––==00==––